



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, बुधवार, 22 फरवरी, 2006/3 फाल्गुन, 1927

---

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 22 फरवरी, 2006

संख्या वि०स०-विधायन-गवर्न० बिल० 1-16/2006.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश असाहाय्यता प्राईवेट ट्रस्ट महा-विद्यालय (शैक्षणिक वर्ष 2003-2004 के लिए प्रवेश का विनियमन और फीस का निश्चय) विधेयक, 2006

(2006 का विधेयक संख्यांक 2) जो आज दिनांक 22 फरवरी, 2006 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

जे० आर० गाजटा,  
सचिव।

## हिमाचल प्रदेश असाहाय्यित प्राईवेट दन्त महाविद्यालय (शैक्षणिक वर्ष 2003-2004 के लिए प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विधेयक, 2006

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

राज्य में असाहाय्यित दन्त महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2003-2004 के लिए राज्य सरकार के कोटे (मैरिट सीटों) में प्रविष्ट छात्रों की फीस का विनियमन और नियतन करने के लिए तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों में उपलब्ध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश असाहाय्यित प्राईवेट दन्त महाविद्यालय (शैक्षणिक वर्ष 2003-2004 के लिए प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 है।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) यह 15 सितम्बर, 2003 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. यह अधिनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से सम्बद्ध असाहाय्यित प्राईवेट दन्त महाविद्यालयों को लागू होगा।

लागू होगा।

3. इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं।

(क) “राजपत्र” से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(ख) “असाहाय्यित प्राईवेट दन्त महाविद्यालय” से कोई भी महाविद्यालय या स्कूल या संस्थान, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो सम्बन्धित वैधानिक निकाय द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त दन्त शल्य चिकित्सा में व्यावसायिक शिक्षा दे रहा हो और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है तथा केन्द्रीय या राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी निकाय से पूर्णतः या भागतः वित्तीय सहायता या सहयोग प्राप्त नहीं कर रहा है अभिप्रेत है;

(ग) “राज्य” से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है; और

(घ) “राज्य सरकार” या “सरकार” से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है।

1956 का  
3.

फीस का 4. किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश या निर्णय या जारी निश्चयन और किसी आदेश, अधिसूचना या अनुदेशों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य विनियमन। में असाहाय्यित प्राईवेट दन्त महाविद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष 2003-2004 के दौरान सरकारी कोटे (मैरिट सीटों) में प्रविष्ट छात्र शैक्षणिक वर्ष 2003-2004 के लिए अधिसूचना संख्या एच0 एफ0 डब्ल्यू0 बी0(एफ0) 5-10/94-लूज, तारीख 15-9-2003 द्वारा जारी फीस संरचना के अनुसार दन्त शल्य चिकित्सा स्नातक के सम्पूर्ण शैक्षणिक पाठ्यक्रम के लिए फीस का संदाय करते रहेंगे।

नियम बनाने की शक्ति। 5. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, और यदि उस सत्र के जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हों या यथोपरोक्त आनुक्रमिक सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई परिवर्तन करती है या सहमत हो जाती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् यथास्थिति, ऐसा नियम ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसे किसी परिवर्तन या बातिलीकरण से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस्लामिक एकेडमिक एजुकेशन वनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक मामले में, तारीख 14-8-2003 को उच्चतम न्यायालय के आदेश सुनाए गए थे। तथापि सितम्बर, 2003 तक फीस संरचना समिति का गठन नहीं किया जा सका, अतः भारत के उच्चतम न्यायालयों के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश में असाहाय्यित प्राईवेट दन्त महाविद्यालयों की फीस 14-8-2003 के पश्चात् फीस संरचना समिति द्वारा नियत की जानी थी। इसलिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एच0एफ0डब्ल्यू-बी0(एफ0) 5-10/94-लूज तारीख 15-9-2003 द्वारा वर्ष 2003-04 के लिए फीस संरचना नियत की गई थी, अर्थात् पचास प्रतिशत राज्य कोटा (मैरिट सीटों) के लिए बीस हजार रुपए और प्रबन्धन सीटों (अदायगी सीटों) के लिए दो लाख पचास हजार रुपए प्रति छात्र/प्रति वर्ष तथापि राज्य सरकार द्वारा नियत फीस को सिविल वाद याचिका संख्या 763/03 नामतः तृषा शर्मा वनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में चुनौती दी गई थी और तत्पश्चात् सिविल वाद याचिका संख्या 22/04, 824/04 तथा 990/04 में, माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2003-04 के लिए नियत फीस अन्तिम होगी और फीस संरचना समिति विचार करेगी कि क्या उसी को स्वीकार किया जाए या वर्ष 2003-04 के लिए पुनः फीस नियत की जाए।

माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के निर्देशानुसार, फीस संरचना समिति द्वारा विवादक पर विचार किया गया था और प्रदेश में असाहाय्यित प्राईवेट दन्त महाविद्यालयों की वास्तविक वर्ष 2003-04 के लिए अन्तिम फीस संरचना, अर्थात् माठू राम निर्मला देवी महाविद्यालय सोलन और भोजिया दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल भूड नालागढ़ के लिए चौरासी हजार रुपए और हिमाचल इन्टीच्यूट ऑफ डेंटल साईंस पांवटा साहिब के लिए पैंसठ हजार रुपए और हिमाचल दन्त महाविद्यालय सुन्दरनगर के लिए तरेसठ हजार रुपए, प्रति छात्र/प्रति वर्ष नियत की गई।

माननीय उच्चतम न्यायालय के मामले नामतः टी0एम0ए0वाई वनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक (2002) 8 एस0सी0सी0 481 में निर्णय को ध्यान में रखते हुए फीस संरचना समिति ने मैरिट सीटों (राज्य कोटा अर्थार्थियों) से कम फीस प्रभारित करने की पद्धति को समाप्त कर दिया है तथा समान/एकरूप फीस दरों की विरचना कर प्रबन्धन सीटों के विद्यार्थियों के प्रवर्गों के बराबर कर दिया है जोकि राज्य कोटे (मैरिट सीटों) में दाखिल किए गए छात्रों से कहीं अधिक उच्चतर हैं। इस कारण से सरकार का पचास प्रतिशत सीटों को मैरिट मुक्त सीटों (राज्य कोटा) रखने और उनसे साहाय्यित फीस प्रभारित करने का उद्देश्य विफल हो गया तथा प्राईवेट महाविद्यालय इसका अनुचित लाभ उठा सकते हैं।

सभी पहलुओं पर समुचित विचार करने के पश्चात् सरकार द्वारा वर्ष 2003-04 के लिए असाहाय्यित प्राईवेट दन्त महाविद्यालयों में पचास प्रतिशत सरकारी सीटों (मैरिट सीटों) के लिए बीस हजार रुपए प्रति छात्र/प्रति वर्ष की फीस संरचना नियत की गई थी जबकि बाद में इस प्रकार गठित फीस संरचना समिति ने समस्त प्रवर्ग के छात्रों अर्थात् मैरिट/अदायगी सीटों हेतु समान पद्धति पर भूतलक्षी प्रभाव से, तरेसठ हजार रुपए से चौरासी हजार रुपए प्रति छात्र/प्रति वर्ष की फीस नियत की।

क्योंकि मैरिट सीटों में पहले से ही प्रविष्ट छात्रों ने बीस हजार रुपए प्रति वर्ष की फीस की रकम को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त असाहाय्यित प्राईवेट दन्त महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु विकल्प दिया और यदि उन्हें इस तथ्य की जानकारी होती कि इन सीटों की तरेसठ हजार रुपए से चौरासी हजार रुपए प्रति छात्र प्रति वर्ष फीस नियत की जाएगी, तो वे इन महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु विकल्प ही नहीं देते। इस लिए शैक्षणिक वर्ष 2003-04 के लिए भूतलक्षी प्रभाव से फीस वृद्धि से छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और शैक्षणिक सत्र 2003-04 में असाहाय्यित प्राईवेट दन्त महाविद्यालयों में मैरिट सीटों के विरुद्ध पहले से ही प्रविष्ट छात्रों तथा उनके माता-पिता में व्याप्त नाराजगी है। इसलिए विभिन्न असाहाय्यित प्राईवेट दन्त महाविद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष 2003-2004 में मैरिट सीटों में प्रविष्ट छात्रों के हितों के संरक्षण के लिए तथा उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए विधान लाने का विनिश्चय किया गया जो राज्य में असाहाय्यित

प्राइवेट दन्त महाविद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष 2003-2004 के लिए राज्य कोटे (मैरिट सीटों) में दाखिल छात्रों की बाबत प्रवेश का विनियमन तथा फीस का नियतन का उपबन्ध करने के लिए है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

वीरभद्र सिंह,  
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

तारीख..... फरवरी, 2006.

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

**हिमाचल प्रदेश असाहाय्यित प्राईवेट दन्त महाविद्यालय (शैक्षणिक वर्ष 2003-2004 के लिए प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विधेयक, 2006**

राज्य में असाहाय्यित प्राईवेट दन्त महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2003-2004 के लिए राज्य सरकार के कोटे (मैरिट सीटों) में प्रविष्ट छात्रों की फीस का विनियमन और नियतन करने के लिए तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों को उपलब्ध करने के लिए विधेयक।

बोरभद्र सिंह,  
मुख्य मन्त्री।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,  
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला :  
तारीख . . . . . फरवरी, 2006.

## AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 2 of 2006.

**THE HIMACHAL PRADESH PRIVATE UNAIDED DENTAL  
COLLEGES (REGULATION OF ADMISSION AND FIXATION  
OF FEE FOR ACADEMIC YEAR 2003-2004) BILL, 2006**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

**A  
BILL**

to provide for the regulation and fixation of fee in Private Unaided Dental Colleges in the State for the academic session 2003-2004 in respect of students admitted against State Government Quota (merit seats) and the matters connected therewith or incidental thereto;

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-seventh Year of the Republic of India, as follows :—

Short title  
and com-  
mencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Private Unaided Dental Colleges (Regulation of Admission and Fixation of Fee for the academic year 2003-2004) Act, 2006.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 15th day of September, 2003.

Applica-  
tion.  
3 of 1956.

2. This Act shall apply to the Private Unaided Dental Colleges affiliated to Himachal Pradesh University established under section 2(f) of the University Grants Commission Act, 1956.

Definitions

3. In this act, unless the context otherwise requires,—

(a) “Official Gazette” means the Rajpatra of Himachal Pradesh;

(b) “Private Unaided Dental College” means a college or a school or an institution by whatever name called, imparting professional education in Dental Surgery approved by or recognized by the concerned statutory body and affiliated to the Himachal Pradesh University and not receiving financial aid or assistance in whole or in part from the Central or State Government or from anybody, under the control of Central or State Government;

(c) “State” means State of Himachal Pradesh; and

(d) “State Government” or “Government” means the Government of Himachal Pradesh.

Fixation  
and  
regulation  
of fee.

4. Notwithstanding anything contained in any order or judgment passed by any competent court or any order, notification or instructions issued, the students admitted against Government quota (merit seats) during the academic year 2003-04 in Private Unaided Dental Colleges in the State shall continue to pay fee for the academic year 2003-2004



according to the fee structure issued *vide* Notification No. HFW-B (F) 5-10/94-loose dated 15-9-2003 for the entire academic course of Bachelor of Dental Surgery.

5. (1) The State Government may, by notification published in the official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

Powers  
to make  
Rules.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislative Assembly while it is in session, for a total period of ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of session in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making any modification in the rule, or agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Supreme Court orders in *Islamic Academic Education Vs State of Karnataka* was pronounced on 14-8-2003 yet the Fee Structure Committee could not be constituted till September, 2003, therefore, as per directions of the Supreme Court of India the fees for private Unaided Dental Colleges in Himachal Pradesh was to be fixed by the Fee Structure Committee after 14-8-2003, therefore, the fee structure for the year 2003-04 was fixed by the State Government *vide* Notification No. HFW-B(F)5-10/94-Loose, dated 15-9-2003, *i. e.* Rs. 20,000/- for 50% State Quota (merit seats) and Rs. 2,50,000/- for 50% Management Seats (Payments seats) per student/per annum. However, the fees fixed by the State Government was challenged in the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh *vide* CWP No. 763/03 titled as *Trisha Sharma Vs State of H. P.* and thereafter CWP No. 22/04, 824/04 and 990/04, the Hon'ble High Court has directed that the fees fixed by the State Government for the year 2003-04 will be provisional and Fee Structure Committee will consider as to accept the same or again fix the fees for the year 2003-04.

As per direction of the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, the issue was considered by the Fee Structure Committee and has fixed the final fees structure in respect of Private Unaided Dental Colleges in Himachal Pradesh for the year 2003-04, *i. e.* Rs. 84,000/- each for Marhurarum Nirmala Devi College, Solan and Bhojia Dental College & Hospital, Bhud Nalagarh, Rs. 65,000/- for Himachal Institute of Dental Science, Paonta Sahib and Rs. 63,000/- for Himachal Dental College, Sundernagar, per student/per annum.

Keeping in view of the judgment of Supreme Court in case titled as *T. M. A. Pai Vs State of Karnataka* (2002) 8 SCC 481 the Fee Structure Committee has done away with the practice of charging less fee from merit seats (State Quota candidates) and has brought at par with categories of students of management seats by framing same/uniform rate fees, which is much higher side for the students admitted against State Quota (merit seats). Due to this reason the purpose of Government to keep 50% seats as free merit seats (State Quota) and charge subsidized fees from them get defeated and the private colleges may get undue benefit.

The fee structure for 50% 'Government seats (merit seats) in Private Unaided Dental Colleges for the year 2003-04 was fixed @ Rs. 70,000/- per student/per annum by the Government after due consideration of all aspects, whereas the Fee Structure Committee so constituted later on fixed the fee ranging from Rs. 63,000/- to 84,000/- per student/per annum with retrospective effect on uniform pattern to all categories of students *i. e.* merit/payment seats.

Since the students already admitted against merit seats opted for admission in the above Private Unaided Dental Colleges keeping in view of the fee amount of Rs. 20,000/- per annum and if they were aware of the fact that the fee against these seats will be fixed ranging from Rs. 63,000/- to 84,000/- per student/per annum, they would not have opted for admission in these colleges. Therefore, the enhancement of fee for the academic year 2003-04 retrospectively, has adversely affected the students and there is widespread resentment amongst the parents and students already admitted against merit seats in Private Unaided Dental Colleges during the academic session 2003-04. Thus, in order to protect the interest of the students admitted against merit seats, during academic year 2003-04 in various private Unaided Dental Colleges and to save their future, it has been decided to bring legislation which seeks to provide for regularization and fixation of fee in respect of students admitted against State Quota (merit seats) for academic year 2003-04 in the private Unaided Dental Colleges in the State.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

VIRBHADRA SINGH,  
*Chief Minister.*

SHIMLA :

*The* .....2006.

**FINANCIAL MEMORANDUM**

Nil

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

Nil

---

**HIMACHAL PRADESH PRIVATE UNAIDED DENTAL COLLEGES (REGULATION OF ADMISSION AND FIXATION OF FEE FOR ACADEMIC YEAR 2003-2004) BILL, 2006**

---

A

**BILL**

to provide for the regulation and fixation of fee in Private Unaided Dental Colleges in the State for the academic session 2003-2004 in respect of students admitted against State Government Quota (merit seats) and the matters connected therewith or incidental thereto.

**VIRBHADRA SINGH,**  
*Chief Minister.*

**SURINDER SINGH THAKUR,**  
*Secretary (Law).*

**SHIMLA :**

*The . . . . ., 2006.*